विकास का धंधा बना लूट का फ़ंदा

फ़रीदाबाद (म. मो.) यूं तो हर सरकारी काम जनता को लूटने का फंदा है, परन्तु विकास कार्यों के नाम पर होने वाली लूट का शायद कोई मुकाबला नहीं। सरकारी महकमा चाहे 'हूडा' हो या नगर निगम या पी डब्लू डी आदि ने विकास के नाम पर खुली लूट मचा रखी है।

सरकारी कॉलोनाइज़र होने के नाते आज 'हूडा विभाग के पास जनता से लूट का बेइन्तहा पैसा पड़ा है। इस पैसे को सरकारी अधिकारी पूरी बेशर्मी के साथ खुल्लम-खुल्ला इस अंदाज़ में लूट रहे हैं कि मानो कह रहे हों कि हम तो ऐसे ही लूटेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताज़ा तरीन उदारहरण सेक्टर 11-12 की विभाजक सड़क का है। सितम्बर 2015 में मैट्रो रेल के उद्घाटन करने जब प्रधानमंत्री मोदी यहां आये थे तो उनके लिये करीब एक-डेढ किलोमीटर की पहले से बनी बनाई सड़क को और बढिया बनाने के नाम पर 80 लाख रुपये खर्च कर दिये गये थे। मात्र 6 माह के भीतर ही सड़क के इस टुकड़े की रोड़ियां बिखरने लगी हैं। एक बरसात ढंग की हो जाने के बाद तो इसका काला रंग ही बहता नज़र आयेगा।

शुकर यह है कि यह काम मात्र 80 लाख में ही किया गया, वरना 8 लाख के इस काम को यदि ये लुटेरे 180 या 280 लाख में भी करा दिखा देते तो कौन पूछने वाला था? क्योंकि पूछ सकने वाले खुद अपने-अपने हिस्से-पत्ति के जुगाड़ में रहते हैं। संदर्भवश, गौरतलब यह भी है कि यह काम इतनी जल्दबाज़ी में किया गया कि रातों में भी काम किया गया। दरअसल यहां एक प्रथा सी बन गयी है कि कोई भी काम समय रहते शुरू नहीं किया जाता। जब समय समाप्त होने लगता है तब काम को शुरू किया जाता है। जाहिर है ऐसे में, संकटकालीन स्थिति खड़ी करके जब काम होता है तो अनाप-शनाप खर्च करने का बहाना तो मिलता है साथ में काम की गुणवत्ता को भी नज़रअंदाज़ करने की सहूलियत रहती है। राजधानी दिल्ली में कॉमनवैल्थ खेलों के लिये भी सारा काम इसी तर्ज पर किया गया था। इसी तरह का एक काम अभी गत पखवाड़े बीके अस्पताल में मुख्यमंत्री खट्टर के आगमन पर हुआ। यहां भी मात्र 200-300 मीटर की पहले से बनी बनाई सड़क पर रातों-रात काम करके लाखों रुपये के वारे न्यारे कर लिये गये। काम तो नगर निगम ने किया था, परन्तु इसके लिये विशेष बजट चंडीगढ़ से आया था जो बाहर की बाहर ही खर्च दिखा दिया गया। ओल्ड फ़रीदाबाद स्थित रेलवे अंडरपास के साइड रैम्प 'हूडा' द्वारा बनाये गये थे जबकि रेलवे ट्रैक के नीचे का असली महत्वपूर्ण कार्य रेलवे द्वारा स्वयं किया गया था। इन रैम्पो को बनाने में हूडा ने 4 वर्ष से अधिक का समय तथा 32 करोड़ से अधिक रुपया व्यय कर दिया। अधिक से अधिक रुपया डकारने के लिये अधिक से अधिक समय भी लगाना जरूरी होता है। उसके बावजूद अभी भी इस अंडरपास का काम सही ढंग से पूरा नहीं हुआ है। रोशनी का प्रबन्ध न होने के चलते दिन में भी यहां रात जैसा अंधेरा रहता है। बरसाती पानी की निकासी का भी प्रबन्ध पर्याप्त नहीं है। इसकी योजना अभी विचाराधीन है। जाहिर है इसके लिये बजट अलग से डकारा जायेगा।

इसी तरह बदरपुर बार्डर से कैली गांव के निकट तक का करीब 30 किलोमीटर लम्बा बाइपास मार्ग बनाने पर भी 130 करोड़ से अधिक खर्च कर दिया गया और पूरा करने की डेड लाइन तो दर्जनों बार बढ़ानी पड़ी। इसके बावजूद ज्योंही इस पर पूरा ट्रैफ़िक चलने लगा, जगह-जगह से सड़क उखड़ने लगी, अब इसे और 'मजबूत' करने के नाम पर अलग से बजट डकारने की योजना विचाराधीन है। इसके साथ-साथ साइकिल ट्रैक के नाम पर अलग से फंड की मांग की जा रही है।

करीब 2 किलोमीटर का एक सज़ावटी साइकिल ट्रैक सेक्टर 11-12 की विभाजक सड़क जो बाइपास को मथुरा रोड से जोड़ती है, के साथ भी बनाने का भी हल्ला सुनाई पड़ रहा है। इसका प्रारंभिक बजट 40 लाख रखा गया है, पूरा कितने में होगा पता नहीं। जब इनकी बनाई कोई सड़क साल भर भी नहीं टिकती तो ये साइकिल ट्रैक कितने दिन टिकेंगे, समय ही बतायेगा। वैसे 20 लाख की आबादी वाले इस शहर में आधे से अधिक आबादी साइकिल से ही चलती है जिसे 2 किलोमीटर के सजावटी ट्रैक की अपेक्षा पूरे शहर में कार्यरत साइकिल ट्रैक चाहियें, जो इस सरकार के एजेंडे में कभी हो नहीं सकते। हां, इनके एजेंडे में तमाम सेक्टरों की मार्केटों में बने बनाये फ़र्शों व ग्रिलों को बार-बार तोड़ना व बनाना ज़रूर है क्योंकि इस धंधे में लूट कमाई सरल व अधिक है।

खट्टर न लिखने से क्या होगा, संघ-बीजेपी तो घोर जातिवादी हैं

-वाई. के. रज्जन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने नाम के साथ लगा खट्टर शब्द यह कहकर हटा दिया कि वह खट्टर के रूप में अपनी पहचान नहीं चाहते। वह हरियाणा में हुए जाट आंदोलन से बहुत आहत हैं और इसीलिए यह फैसला लिया है। लेकिन इसे हटाने से पहले उन्होंने हरियाणा विधानसभा में एक गढ़ा हुआ किस्सा सुनाया जो निहायत ही फर्जी है। इसी से पता चलता है कि संघ वाले हर चीज बहुत सोची समझी रणनीति के तहत करते हैं। खट्टर की इस पहल पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आना चाहिए। जब मनोहर लाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी आलाकमान (इसे प्रधानमंत्री पढ़ें) ने पैराशूट से उतारा तो उनके चमचों ने भाड़े के मीडिया में खबरें छपवाईं कि अभी तक हरियाणा की नेतृत्व ज्यादातर जाट मुख्यमंत्री करता रहा है तो इस बार एक पंजाबी को बीजेपी ने हरियाणा में भेजने का फैसला किया है। यह भी कहा गया कि बीजेपी राज्य को जाट पॉलिटिक्स से छुटकारा दिलाना चाहती है इसलिए यह कदम उठाया गया है। यहां पर एक और तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाता चलूं। मनोहर लाल करनाल की जिस सीट से मैदान में विधानसभा का चुनाव लड़ने उतरे, वहां पर पूरे चुनाव के दौरान उन्हें पंजाबी नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया और पंजाबियों से वोट मांगे गए। वहां के लोगों ने मनोहर लाल को इसी रूप में वोट भी दिया क्योंकि जब नतीजे घोषित हुए तो गैर पंजाबी प्रत्याशियों को बहुत मामूली वोट मिले। बता दें कि करनाल से ही पंजाब केसरी (दिल्ली) का मालिक अश्विनी कुमार मित्ना भी बीजेपी सांसद हैं। उन पर अभी तक ये आरोप है कि उन्होंने मनोहर को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर मनोहर के सीएम बनने पर विद्रोह की धमकी दी। अश्विनी आज भी मनोहर लाल की जड़ें खोदने का कोई मौका खोता नहीं है।

अब असल मुद्दे पर आते हैं...मनोहर लाल को हरियाणा की कमान सौंपते वक्त जातिवाद का घिनौना कार्ड किसने खेला, यह अब आपको समझ में आ गया होगा। आरएसएस पूरी तौर पर जातिवाद की विचारधारा में विश्वास करती है। उसके अध्यक्ष एकाध अपवाद को छोड़कर ब्राह्मण ही बनते रहे हैं। आरएसएस का संघचालक इलाहाबाद के कुंभ में महिलाओं से अपने पैर धुलवाता और पैर पर हाथ लगवाते हुए देखा जा सकता है। वह फोटो फेसबुक पर पत्रकार दिलीप मंडल की वॉल पर आज भी देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरएसएस भी उच्च जाति के दबदबे की विचारधारा में विश्वास करता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कम-ज्यादा करता रहता है। मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाते वक्त संघ परिवार ने जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रचार किया वो था कि मोदी ओबीसी हैं और चाय बेचते थे। संघ ने यह प्रचार नहीं किया कि गुजरात नामक दंगों की प्रयोगशाला में मोदी को सीएम के रूप में जिस तरह इस्तेमाल किया गया, अब वो प्रयोग पीएम बनाके किया जाएगा। अगर संघ जातिवाद में विश्वास नहीं करता है तो फिर उसके सांसद या मंत्री क्षत्रिय सभा, कायस्थ सभा, कुर्मी सम्मेलन, शाक्य पिछड़ा सम्मेलन, प्रजापति संघ, कुम्हार संघ, ब्राह्मण सम्मेलन, सरयू ब्राह्मण सभा, गंगा ब्राह्मण सभा जैसे आयोजन क्यों करवाते हैं या उनमें जाते क्यों हैं। उनका केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जिसका नाम मुजफ्फरनगर दंगों में आया, रोहतक में जाटों के सम्मेलन में क्यों हिस्सा लेता है, वह उस मंच से सैनियों को क्यों ललकारता है....केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह उसी जाट महासभा के कार्यक्रम में क्यों बालियान की हां में हां मिलाते हैं और आरक्षण की मांग पर मुहर लगाते हैं....और बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी रोहतक में ही क्यों सैनी सम्मेलन बुलाकर जाटों को ललकारता है...सैनी क्यों कहता है कि जाटों से निपट लेंगे...आखिर ये जातिवाद का जहर कौन फैला रहा है। पहले कांग्रेस यही काम करती थी, अब संघ और बीजेपी उसी फसल को बोने में लगे हैं। फिलहाल तो संघ और बीजेपी के अलावा कोई दूसरा जातिवादी राजनीति कर ही नहीं रहा है। कौन नहीं जानता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हुए विश्व सूफी सम्मेलन में अल्लाह के 99 नाम बताने क्यों पहुंचे...दरअसल, संघ और बीजेपी में कोई भी कदम इन दिनों बिना फायदे-नुकसान को गिने नहीं उठाए जा रहे। खट्टर ने भी वही किया। बल्कि मनोहर लाल ने खट्टर हटाकर खुद को भजनलाल श्रेणी का नेता बनाने की चाल चली है। भजनलाल अब जीवित नहीं हैं, उनकी कमियों, भ्रष्टाचार को यहां गिनाने से कोई फायदा नहीं होगा लेकिन खट्टर चाहते हैं कि वो अगला भजनलाल बन जाएं।

लेकिन पब्लिक तो संघ और बीजेपी के मुखौटों को अच्छी तरह जानती है। उसने सोशल मीडिया पर इस पर खूब खिल्ली उड़ाई। वाट्सऐप पर चुटकुले चले। किसी ने कहा कि यह खटराग है, आखिर कब तक बजेगा...किसी ने कहा, क्या खटखट लगा रखा है...कोई बोला खटरपटर अब नहीं चलेगा....किसी ने फरमाया, खट-खट के जीना भी कोई जीना है...किसी ने सोचा, खटरनाक सपने का अंत...यानी खट्टर शब्द के हटाने पर जो संघ और बीजेपी ने सोचा था, वैसा कुछ नहीं हुआ।

महान उपन्यासकार, नाटककार शेक्सपियर बरसों पहले लिख गए हैं कि नाम में क्या रखा है....तो श्रीमान, खट्टर हटाने से क्या आरएसएस और बीजेपी जातिवाद की राजनीति छोड़ देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। इसलिए हरियाणा के लोगों को संघ और बीजेपी को लेकर कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए।

मैट्रो रेल से रोडवेज घाटे में ?.

फ़रीदाबाद (म.मो.) मैट्रो रेल सेवा शुरू होने से जहां स्थानीय जनता को यातायात के मामले में राहत मिली है वहीं हरियाणा रोडवेज़ परेशान है। सदैव घाटे में चलने वाले इस विभाग ने अब घाटे का ठीकरा मैट्रो रेल के सिर पर फ़ोड़ना शुरू कर दिया है। मज़े की बात यह है कि जो ऑटो रिक्शा पहले बल्लबगढ़ से बदरपुर बार्डर तक सवारियां ढोने का काम करते थे, उन्हें इस मैट्रो रेल से कतई कोई परेशानी नहीं हुई। वे अब भी उतना ही कमा रहे हैं, कोई छोड़कर भागा नहीं बल्कि रोज़ नये-नये ऑटो इस धंधे में प्रवेश कर रहे हैं।

दरअसल घाटे का कारण मैट्रो नहीं बल्कि सरकारी भ्रष्टाचार व नालायकी है। करीब 3 साल पूर्व जब इस शहर में 200 बसें बतौर सिटी 'बस सर्विस' रोडवेज़ द्वारा उतारी गयी थीं तो यह लगा था कि अब बेचारे ऑटो वाले कहां जायेंगे? लेकिन ऑटो वाले न केवल कायम हैं बल्कि खूब फ़ल-फूल रहे हैं, जबकि उन 200 बसों में से आधे से अधिक कबाड़ हो चुकी हैं और उन्हें चलाने से जो घाटा हुआ वह अलग। कारण? कारण बड़ा स्पष्ट है। ऑटो वाला यदि किराये पर ऑटो लेता है तो उसे शाम तक उसका किराया जरूर कमाना है, कर्ज लिया है तो ब्याज सहित उसकी किश्त चुकानी है और बाल-बच्चों का भरण-पोषण भी इसी से करना है। इसलिये उसे तो काम करके, कमाना ही है। यदि सिटी बसें या मैट्रो चल गयी है तो वह ढूंढता है कि सवारी कहां से और कैसे पकड़नी हैं।

दूसरी ओर रोडवेज़ की बसें खरीदने के लिये जनता से टैक्स वसूला जाता है। बसें तथा अन्य खरीदारी पर अफ़सर व नेता कमीशन डकारते हैं। [सवारी ढोकर मुनाफ़ा कमाने की, इस महकमे में न तो किसी की इच्छा है न जरूरत।] बसें चलें न चलें घाटा हो या नफ़ा हो अफ़सरों का वेतन पक्का। पक्के वेतन से बचने के लिये सरकार ने असल काम करने वाले-ड्राइवर, कंडक्टर दिहाड़ी पर रखने लगे हैं। बसों को चालू हालत में रखने के लिये वर्कशॉप में न तो मिस्त्री रहे न सामान। आवश्यक सामान जो पहले डिपो का जी एम खरीद लेता था वह अब चंडीगढ़ में बैठे मंत्री एवं उच्चाधिकारी खरीदते हैं क्योंकि इससे मिलने वाला कमीशन सीधा और एक मुश्त उन्हें मिल जाता है।

इसके अलावा राजनीतिक संरक्षण विशेषकर स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल के संरक्षण में निजी बसें व अन्य वाहनों ने बल्लबगढ़ के बस अड्डे पर पूरा कब्ज़ा कर रखा है। रोडवेज़ की बसें बेशक खाली खड़ी रहें लेकिन निजी वाहन खूब कमा रहे हैं। रोडवेज़ के स्थानीय व चंडीगढ़ में तैनात अफ़सर जनता की नहीं बल्कि कृष्णपाल की नौकरी कर रहे हैं।

'सख्त' आदेशो के बावजूद एनआईटी में काले धंधे जारी

फरीदाबाद (म.मो.) नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर हनीफ कुरैशी ने अपने तमाम अधिकारियों, सभी थाना-चौकी इंचार्ज को ज़िले में कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए थे साथ ही शहर में गोरखधंधे करने वालों पर नकेल कस जनता को सुरक्षित माहौल देने के आदेश ज़ारी किए हैं। साथ ही शहर में गोरखधंधे करने वालों पर नकेल कस जनता को सुरक्षित माहौल देने का आदेश भी दिए थे। लेकिन उनके ये आदेश दस दिन में ही हवा हो गए। जिसकी पोल गली-मोहल्लों में सट्टेबाज व शराब माफ़िया खुलेआम धंधा कर खोल रहे हैं।

इसी कड़ी में थाना एनआईटी क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक शराब माफ़िया रोज़ाना लाखों रुपये की अवैध शराब बेच रहे हैं। एनएच 5 के सी ब्लॉक व गांधी कॉलोनी में 1 दर्जन से अधिक सट्टेबाज सट्टे की पर्चियां बेच कर स्कूली बच्चों व युवाओं को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। वहीं 3 नं. चौकी से चंद कदम की दूरी पर डीएवी कॉलेज के ठीक सामने बने पार्क में अवैध शराब का धंधा दिन-दिहाड़े हो रहा है।

वहीं 3 नं. चौकी के अन्तर्गत आने वाली राहुल कॉलोनी में करीब एक दर्जन से अधिक शराब माफ़िया अवैध शराब व सट्टे की पर्चियों का धंधा जमकर चला रहे हैं। दूसरी तरफ़ एनएच 5 के सी जे एम के एन ब्लॉक भगत सिंह कॉलोनी में आधा दर्जन शराब तस्कर रोज़ाना लाखों रुपये की अवैध शराब बेच कर सी पी के आदेशों की हवा निकालते नज़र आ रहे हैं। जबकि ये काम कोई चोरी-छिपे न ही बल्कि दिन-दिहाड़े हो रहा है। इसी एन एच 5 के फ्रुटगार्डन में वेश्यावृत्ति का धंधा भी पुलिस संरक्षण में जमकर चल रहा है। एन एच 5 दयानंद वूमेन कॉलेज रोड पर खुलेआम असामिजक तत्वों का जमावड़ा सारा दिन रहता है। व कॉलेज टाईम पर इन्हें आसानी से गुण्डागर्दी करते देखा जा सकता है। ये तत्व सारा दिन बाइक पर 2-3 एक साथ बैठकर तेज शोर-शराबा करते हुए हंगामा मचाते रहते हैं। स्थानीय लोगों का जीना दुभर कर रखा है। अगर कोई स्थानीय निवासी इनका विरोध करता है तो ये गुण्डे बड़ी बेहरमी से पिटाई करने से भी परहेज नहीं करते।

हिन्द और हिंदुत्व में फर्क

हिन्द के हीरो, अंग्रेजों की जेल में कैद भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को कहा कि जब बरतानवी हुकूमत की अदालत ने उन्हें अंग्रेजी राज के विरुद्ध युद्ध करने का दोषी करार दिया है तो उन्हें, सुखदेव और राजगुरु को सामान्य कैदी के रूप में फांसी देने के बजाय फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली से उड़ाया जाय, जबकि हिंदुत्व के हीरो सावरकर ने अंडमान जेल से अंग्रेजी सरकार को प्रार्थना भेजी थी कि वे आगे से कभी भी बरतानवी राज के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे बशर्ते उन्हें अंडमान से मुख्य भूमि की किसी जेल में भेज दिया जाय और जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाय, 1924 में रिहायी के बाद सावरकर ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कभी चूं तक नहीं की।